



समृद्ध एवं प्राचीन हस्तकला “कुम्हारी कला” को राज्य में बढ़ावा दिया जाए : मुख्यमंत्री



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री ने कुम्हार हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सचिवालय में मिट्टी के गिलास में चाय पी। मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। कुम्हारों को उन्नत किस्म के मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। कुम्हार हस्तकला को सीएम स्वरोजगार योजना में भी

जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुवार को सचिवालय में “कुम्हारी कला” को पुनर्जीवित करने को लेकर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में कुम्हारी कला को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुम्हारी कला समृद्ध एवं प्राचीन हस्तकला है। उत्तराखण्ड में अनेक परिवार इस कला से जुड़े हैं। भारत सरकार की “कुम्हार सशक्तिकरण योजना”

का उद्देश्य कुम्हारी कला को पुनर्जीवित करना एवं समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक कुम्हार समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त कर विकास की मुख्यधारा में वापस लाना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कुम्हारों को उन्नत किस्म के मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध हो, इसके लिए ऐसी मिट्टी वाली भूमि



का चिन्हीकरण किया जाए। चिन्हित भूमि से कुम्हारों को आवश्यकतानुसार एवं मानकों के हिसाब से निःशुल्क मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार हस्तकला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में मिट्टी से बने गिलासों में चाय देने की शुरुआत की जाए। इसे व्यापक स्तर पर प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों ने सचिवालय में मिट्टी के गिलासों में चाय पीकर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि 03 माह में कुम्हारी कला की अगली बैठक आयोजित की जायेगी, कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्या प्रयास किये गये, इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने

कहा कि कुम्हारी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए। इस विद्या से जुड़े लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें हर सम्भव मदद दी जाए। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर हाटों में हस्तकला से जुड़े लोगों को भेजा जाए। कुम्हारी कला को राज्य में बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो। उन्होंने कहा कि कुम्हार हस्तकला इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है। कुम्हार हस्तकला को सीएम स्वरोजगार योजना में भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी है, दीपावली के पर्व पर कुम्हारों द्वारा निर्मित दिये एवं अन्य उत्पादों की खरीद के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाए।

भारतीय सेना को मिलेंगे 288 युवा अफसर, 8 मित्र देशों के 89 कैडेट भी होंगे पास आउट

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। परेड के बाद 377 जेंटलमैन कैडेट देश-विदेश की सेना का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थलसेना को मिलेंगे। अन्य 89 युवा सैन्य अधिकारी आठ मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान व तंजानिया की सेना का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही सैन्य अकादमी के नाम देश-विदेश की सेना को 64 हजार 145 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ जाएगा। इनमें मित्र देशों को मिले 2813 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल आफिसर कर्मांडूषडग इन चीफ ले. जनरल अमरदीप सिंह भिंडर बतौर रिव्यूइंग आफिसर पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। वह शुरुवार को अकादमी पहुंच गए हैं। देश-विदेश के गण्यमान्य लोग और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी अकादमी पहुंचे हैं। पासिंग आउट परेड के मद्देनजर अकादमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। चप्पे-चप्पे पर सेना के सशस्त्र



जवान तैनात हैं। अकादमी परिसर के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के पास है। परेड के दौरान शनिवार सुबह पांच बजे से 11 बजे तक पंडितवाड़ी से लेकर प्रेमनगर

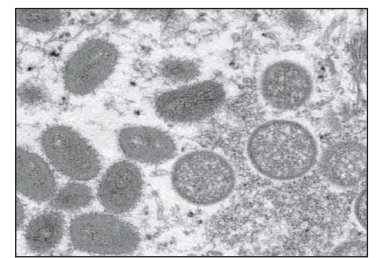
तक जीरो जोन रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (चकराता रोड) से गुजरने वाला यातायात प्रेमनगर व बल्लपुर से डायवर्ट रहेगा।

रुड़की में मंकीपाक्स का संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट सामान्य, मोहम्मदपुर में एक 38 वर्षीय पुरुष में मिले थे लक्षण

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुड़की। मोहम्मदपुर में शुरुवार को मंकीपाक्स वायरस के एक संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। जांच रिपोर्ट में मंकीपाक्स की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मरीज को आटो इन्फ्यूज डीजीज हुई है। जिसके कारण उसमें मंकीपाक्स जैसे लक्षण देखने को मिले।

शहर के मोहम्मदपुर में एक 38 वर्षीय पुरुष में मंकीपाक्स जैसे लक्षण मिलने पर शुरुवार को सिविल अस्पताल रुड़की से डा. नीतिश कुमार चार सदस्यीय टीम के साथ मोहम्मदपुर पहुंचे। टीम ने संदिग्ध मरीज की जांच की और उसका ब्लड, गले और स्किन से सैंपल लिया। मरीज के पूरे शरीर में दाने हुए थे। साथ ही उन्हें खुजली और कमजोरी की भी शिकायत थी। मरीज ने पूछताछ में बताया कि वह एक फैक्ट्री में काम करता है। पिछले दो माह से उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और न ही वह किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आया है। एसीएमओ डा. पंकज जैन ने बताया कि मरीज एवं उसके स्वजन से पता



चला है कि मरीज को खाना खाने के बाद यह दिक्कत हुई थी। बता दें कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप समेत कई देशों में मंकीपाक्स फैल चुका है। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. शैलजा भट्ट ने मंगलवार को सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश जारी किए। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिन लोग में बुखार के साथ शरीर पर लाल चकते जैसे लक्षण दिखाई देते हों, वह तुरंत अपनी नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें।

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 21 दिन में किसी ऐसे देश की यात्रा की है, जहां हाल ही में मंकीपाक्स के मामले मिले हैं, या फिर इस बीमारी के संदिग्ध मामलों की पहचान हुई है, वह भी चिकित्सक से जांच कराएं।

केंद्र सरकार ने बदला सोना खरीदने का नियम, खरीदने से पहले पढ़ें नियम



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सोना खरीदते वक्त हम सबके मन में सवाल उठता है कि जो सोना हम खरीद रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं। उस सोने में कितनी मिलावट है और कितना खरा सोना है। सोने की कीमत तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन उस कीमत में हमें कितना शुद्ध सोना मिल रहा है ये सब सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं, लेकिन अब आपको सोना खरीदते वक्त इसकी शुद्धता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई तो वहीं 1 जून से 32 और जिलों में BIS हॉलमार्क के साथ सोना बेचना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे में सोने के

गहनों पर एक नंबर को चेक कर हम उसकी शुद्धता को जांच सकते हैं।

सोना बेचने का नया नियम

सोना खरीदने वालों के लिए ये जरूरी खबर है। 1 जून से सोना खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है। 1 जून 2022 से सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत 32 और नए जिलों को जोड़ दिया गया है। यानी जिन जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है उन जिलों में अब 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के आभूषण ही बेचे जा सकेंगे।

जरूर चेक करें तीन अंकों का ये नंबर

सोना बेचने वाले ज्वैलर्स को अब सिर्फ हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदना होगा। उनके लिए ये अनिवार्य है तो वहीं सोना खरीदने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ज्वेलरी खरीदते वक्त वो सोने का कैरेट, हॉलमार्क के निशान और हॉलमार्क के नंबर जरूर चेक कर लें। सोने की शुद्धता हॉलमार्क के तीन नंबर 24 कैरेट शुद्धता -99523 कैरेट शुद्धता -95822 कैरेट शुद्धता -91620 कैरेट शुद्धता -83318 कैरेट शुद्धता -75014 कैरेट शुद्धता -585

चेक करें ये निशान

खरे सोने की शुद्धता को हॉलमार्किंग सत्यापित करता है। ज्वेलरी में कितना सोना है

ये उसकी हॉलमार्किंग के नंबर से तय होगा। वहीं सोने पर हॉलमार्किंग नंबर के साथ-साथ BIS हॉलमार्क का त्रिकोणा निशान भी होता है, जिसे खरीदारी करते वक्त चेक करना जरूरी है। हर सोने की बिस्किट और आभूषण पर खास चिन्ह बने होते हैं। जिसकी मदद से ये आप जांच सकते हैं कि उसमें कितना सोना है।

सोने की गारंटी

सोने के गहने पर तीन चिन्ह होते हैं, जिसे आपको खरीदते वक्त जरूर चेक करना चाहिए। इन जिनहों में

BIS लोगोशुद्धता / सुंदरता ग्रेड6 अंकों का अल्फान्यूमरिक कोड(HUID)

सोना खरीदने पर लागू होगा ये नया नियम



Uttarakhand: प्रदेश में एक जुलाई से प्लास्टिक की सभी चीजों पर बैन, पढ़ें गाइडलाइन



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

प्रदेश में एक जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही ईयर बड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट बिकेंगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी

किए हैं। निर्देशों के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। दरअसल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद प्रदेश में 75

माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसके तहत निदेशालय ने सभी निगम, निकायों को पत्र भेजकर पुरानी 50 माइक्रोन की गाइडलाइंस में संशोधन करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।

13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा। प्लास्टिक की इन चीजों पर एक जुलाई से लगेगा जुर्माना प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सचिव सिंचाई हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को सचिव जल संसाधन भारत सरकार की अध्यक्षता में तथा नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य की योजनाएं निवेश स्वीकृति हेतु इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस की 17वीं बैठक में प्रस्तुत की गई।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की जमरानी बांध परियोजना लागत रु० 2584.10 करोड़ के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90:10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र ही पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किए जायेंगे। परियोजना से 57065 है० अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एम०सी०एम० पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।



परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति केबिनेट में स्वीकृति हेतु रखी जाएगी तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।



मुख्यमंत्री धामी का विकल्प रहित संकल्प पूरा करने में जुटे है आईएएस बृजेश कुमार संत

जेई, सुपरवाइजर और आर्किटेक्ट्स का कोकस तोड़ डाला



■ नक्शा पास होने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी करते हुए आवेदक को अधिकार दिया कि वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पल पल पर स्वयं नजर रखें

■ इंजीनियरों और स्टाफ के मान सम्मान पर खास तवज्जो दी, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया।

■ मसूरी को नाम की नही वास्तविक पहाड़ों की रानी बना दिया

■ एमडीडीए ने आवासीय नक्शे के लिए 15 कार्यदिवस और व्यवसायिक नक्शे के लिए 30 कार्यदिवस की अधिकतम सीमा तय की

■ नक्शा पास करने में त्वरित गति से काम किया मात्र 2 माह में 2100 से घटकर 400 रह गई पेंडेंसी

■ राजस्व में निर्धारित सीमा से 27% प्रतिशत अधिक राजस्व इकठ्ठा किया

■ एमडीडीए में दलालों के प्रवेश को चिन्हित करने की गोपनीय व्यवस्था लागू करके प्रतिबंधित किया और छवि सुधारी

■ आवासीय समस्याओं के निस्तारण के लिए सार्थक प्रयास, 186 HIG, 33 MIG और 104 LIG मकान रेडी टू मूव

■ अवैध निर्माणों पर चलाया हथौड़ा और अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं ध्वस्त



मो.सलीम सैफी, समूह संपादक
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

IAS ... इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो हैं एक ऐसा ख्वाब जो देश के लाखों युवा दिलों में पलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में नौकरी पाना भारत के अधिकांश युवाओं के लिए एक सपना है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में आप केवल आकर्षक व्यक्तित्व ही नहीं बनते बल्कि आपको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और कई निर्णायक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाना होता है।

एक कुशल प्रशासक के तौर पर आपके पास शक्तियों के साथ समाज और सरकार के साथ साथ लोक कल्याण की गंभीर जिम्मेदारियां भी आती हैं। ऐसी ही अहम जिम्मेदारी को आज निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से निभा रहे हैं उत्तराखंड के सीनियर आईएएस अफसर ब्रजेश कुमार संत

अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा, लोगों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने की समझ, आधुनिक संचार कौशल के साथ पारदर्शी न्याय व्यवस्था को बनाने में आज IAS ब्रजेश कुमार संत का नाम उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़े अदब और भरोसे से लिया जाता है। तभी तो प्रदेश की सरकार में जब बड़ी और अहम जिम्मेदारी देने के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट की बात होती है तो सरकार में सबकी पहली पसंद के अधिकारियों में ब्रजेश कुमार संत का नाम भी मस्तिष्क में उभरता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर IAS संत की बेहतरीन कार्यशैली ने न सिर्फ विभाग की छवि को संवारा है बल्कि लोगों में एक भरोसा भी कायम किया है।

जब हम पुराने लोगों से बात करते हैं तो एमडीडीए के प्रति उनके अनुभव कड़वे और तकलीफदेह नजर आये क्योंकि नक्शा पास करवाना हो या विवादित निर्माण कार्यों से जुड़ा मसला सुलझाना रहा हो लोग एडिआं रगड़ते हुए अपनी जेबें ढीली करके भी राहत पाने को लंबा चक्कर लगाने को मजबूर थे। लेकिन आज वो कॉकस टूटा है, फरियादियों को न्याय मिल रहा है क्योंकि विभाग की कमान सम्हालते ही उपाध्यक्ष संत ने दफ्तर में फैले कुछ खास आर्किटेक्ट, जेई और बाबुओं की मनमानियों और सांठगांठ पर कडा प्रहार करते हुए एक पारदर्शी, जन सुलभ वातावरण का निर्माण किया है जहाँ अब प्राधिकरण से जुड़े मामलों पर आवेदकों को कम से कम समय में बड़ी आसानी से राहत भी



मिल रही है और अंदर बाहर का भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है।

बीते जुलाई माह में कार्यभार ग्रहण करने के बाद न्यूज़ वायरस के साथ खास बातचीत में ब्रजेश संत ने कहा था कि मास्टर प्लान को लागू करवाने पर उनका विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा पारदर्शिता और लोगों को सहूलियत देने पर जोर दिया जाएगा। प्राधिकरण आने वाले लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उन्होंने नक्शा पास करने में लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर करने और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने के निर्देश भी पहली मीटिंग में दे दिया थे। जिसका असर आज न सिर्फ विभाग की कार्यशैली में बल्कि फाइलों के तेजी से हो रहे निपटारे में नजर आ रहा है।

इस बदलाव को लाने में ब्रजेश कुमार संत ने किस तरह का सिस्टम तैयार किया ये पूछने पर वो बताते हैं कि देश की मोदी सरकार हो या प्रदेश की धामी सरकार सबका एक ही लक्ष्य है आम आदमी को सहज और सुलभ न्याय देना और पारदर्शिता के साथ सरकार की

योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुँचाना लिहाजा उन्होंने भी प्रदेश की धामी सरकार के इस विजन को आगे बढ़ाया है और विकल्प रहित संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।

एक अन्य सवाल के जवाब में संत कहते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन और टीम को मोटीवेट करने का हुनर तो उन्हें अपने घर में बचपन से ही मिलने लगा था। आपको यहाँ बता दें कि आईएएस संत के पारिवारिक सदस्यों में बड़ी संख्या वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स की रही है और है, अपने ब्यूरोक्रेट पिता के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ही ब्रजेश संत ने कुशल प्रशासनिक प्रबंधन के गुर सीखे हैं।

न्यूज़ वायरस ने जब उनसे सवाल किया कि धामी सरकार की योजनाओं को धरातल पर साकार करने के लिए बेहद व्यस्त और बड़ी जिम्मेदारी को कैसे सफलतापूर्वक निभा रहे हैं तो वीसी संत ने कहा कि एक IAS अधिकारी सरकार और नागरिकों के बीच सेतु का काम करता है; वह लोगों के बीच सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अपने पद पर होते हुए, हमे उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल का

प्रदर्शन करना चाहिए। इसीलिए जब उन्हें एमडीडीए जैसी बेहद खास महकमे की कमान सौंपी गयी तो उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम को लोगों के लिए बेहतर करने के लक्ष्य की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज विभाग के निष्ठावान और मेहनती अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियरों के बीच एक ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ से उन्हें संतुष्टि है कि राज्य की धामी सरकार और स्थानीय नागरिकों के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं।

देहरादून में मौजूद एमडीडीए में आज जिस तरह से फाइलों की रफ्तार बढ़ी है उसमें अधिकारियों की भूमिका पर पारदर्शिता आई है और विवादित अथवा नवीन निर्माण कार्यों से जुड़े मामले के साथ साथ भवन निर्माण के नक्शों का अप्रुवल लेना हो, तो आम लोगों को सुखद अनुभव हो रहे हैं कि टीम की कमान अगर काबिल और कुशल हाथों में होगी तो कामयाबी भी मिलेगी और पुष्कर सिंह धामी सरकार का मकसद भी सफल होगा।



UK Budget 22 : कर्ज के बोझ से कराहते उत्तराखंड को युवा सीएम धामी से उम्मीद



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब नए राज्य उत्तरांचल का अस्तित्व बना तो पहाड़ के विकास की उम्मीद की जा रही थी। जैसे जैसे वकूत गुजरा गढ़वाल और कुमायूँ के लोगों को पहाड़ पर विकास तो सुस्त रफ़्तार में चढ़ता नज़र आया उसके उलट कर्ज का बोझ तेज़ी से चढ़ने लगा। आज हालात ये हैं कि प्रदेश की हालत इस बोझ से कमज़ोर हो चली है।

पिछले 22 सालों में 4 हजार करोड़ का कर्जा अब एक लाख करोड़ की तरफ बढ़ चुका है... खराब वित्तीय हालातों का अंदाजा

इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी लोन ले रही है... अब धीरे-धीरे कर्मचारियों को तनखाह देने के भी सरकार को लाले पड़ने लगे हैं। इन सबके बीच युवा मुख्यमंत्री धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्ज को तेज़ी से और जल्द से जल्द कम करने की भी है। जिसके लिए नए नए उपाय भी अपनाने की ज़रूरत है। नए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी इस चुनौती से जीतना होगा क्योंकि 7 जून को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश धामी सरकार पेश करने जा

रही है। सबकी नज़रें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि सरकार के इस बजट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में वित्तीय हालत गड़बड़ाए हुए हैं और सरकार के फैसले राज्य के भविष्य को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में प्रदेश के मौजूदा वित्तीय हालात पर नज़र दौड़ाए तो फिलहाल सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है...

धामी सरकार के लिए बजट पेश करना बड़ी चुनौती है अर्थ जगत के जानकार कहते हैं कि अब तक की तमाम सरकार राज्य में

राज्य पर इस तरह है कर्ज (राशि करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	ऋण राशि
2019-20	65,982
2020-21	73,478
2021-22	85,486

राजस्व बढ़ोतरी को लेकर कुछ खास फैसले नहीं कर पाई और अब उत्तराखंड केंद्र सरकार की वित्तीय मदद पर आकर टिक गया है... वैसे धामी सरकार के लिए यह बजट बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार के पहले बजट सत्र में युवाओं को रोजगार से लेकर तमाम विकास की योजनाओं पर कुछ बड़े फैसले की दरकार है... उत्तराखंड में कुल 44 हजार 173 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है... जबकि कुल बजट में से करीब 65 फीसदी से ज्यादा तनखाह पेंशन और लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में

खर्च हो जाते हैं... राज्य में यह रकम करीब 30 हजार करोड़ रुपए होती है... आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पिछले साल के बजट में ही करीब 13 सौ करोड़ का घाटा प्राप्त राजस्व के मुकाबले राज्य को हुआ... अब प्रदेश की नज़र एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम पर टिकी है।

जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री अग्रवाल धामी सरकार का बजट पेश करेंगे तो उसमें बढ़ते कर्ज की चुनौती से उबरने का कोई पुख्ता और प्रभावी रोड मैप भी नज़र आया ऐसा अर्थ जगत के जानकार को भरोसा है।

मुख्यमंत्री आवास परिसर में लीची सहित अन्य फलदार पेड़ों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

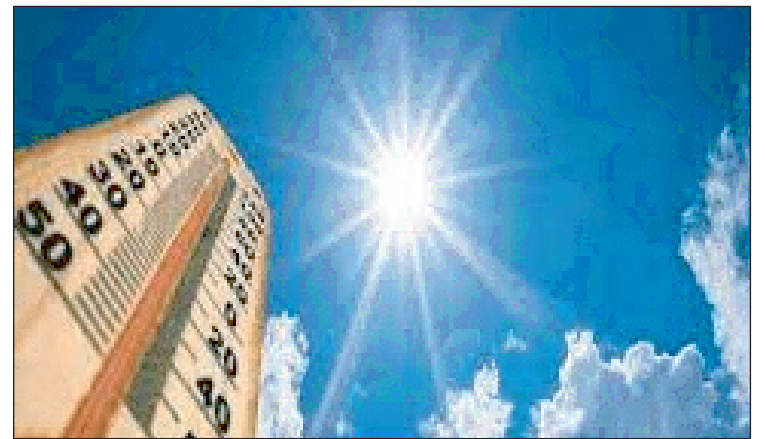
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित लीची के पेड़ों से लीची तोड़ने की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि देहरादून की लीची के लिये भी पहचान रही है। देहरादून की यह पहचान बनी रहे इसके लिये अधिक से अधिक लीची के पेड़ लगाए जाने की उन्होंने ज़रूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जन जागरूकता पर भी ध्यान दिया जाए।

फलदार पेड़ लगाने के लिए जनजागरूकता की भी बताई ज़रूरत।

मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को इसके लिये पहल करने को कहा। राजकीय परिसरों आवासों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में लीची सहित अन्य फलदार पेड़ों के लगाये जाने के प्रयास किये जाने के लिये जनभागीदारी की भी उन्होंने ज़रूरत बतायी।

प्रभारी उद्यान मुख्यमंत्री आवास दीपक पुरोहित ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास परिसर एवं उद्यान निदेशालय परिसर में स्थापित फलदार पेड़ों की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष मार्च में तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि से समस्त फलों पर कुप्रभाव पड़ा है। पिछले एक सप्ताह में तापमान में जो वृद्धि हुई है, उससे लगभग 25 प्रतिशत लीची फल फटने की समस्या आयी है।

उत्तराखंड के इन जिलों में मिलेगी गर्मी से राहत, मैदान में धधकेगी धूप



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

क्या पहाड़ और क्या मैदान ? उत्तराखंड का हाल गर्मी ने बेहाल कर दिया है। सुबह हो या देर शाम या फिर रात न हवा का कोई झोंका राहत दे रहा है और न ही बारिश की बूँद गिरती नज़र आ रही है। पर्यटक हों या स्थानीय लोग उत्तराखंड में गर्मी और बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। मौसम शुष्क होने की वजह से लोगों को लू की थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज मौसम करवट ले रहा है। आज खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग की मानें तो आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं, राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। जबकि, कुछ स्थानों में दिन के समय तेज सतही झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी है। मतलब आप ये मान कर



चलिए कि फिलहाल अभी मैदानी जिलों के लोगों को धधकती धूप की तपिश कुछ समय और झेलनी पड़ेगी। वहीं, तापमान की बात करें तो आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 40°C और न्यूनतम तापमान 25°C रहेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 व्यक्तियों व संस्थाओं को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से किया सम्मानित



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज को दस्तावेज के रूप में संकलित कर राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा। इन बेस्ट प्रैक्टिसेज को राज्य सरकार के स्तर पर भी क्रियान्वित किया जाएगा। एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सराहनीय काम करने के लिये एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सभी को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे। आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड को साकार करने के लिए जन सहयोग आवश्यक है। बहुत सी संस्थाएं और व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। ये सभी राज्य के विकास के ब्रांड एम्बेसेडर हैं। उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में इकोलॉजी और इकोनोमी में संतुलन बनाते हुए काम करना है। पर्यावरण और विकास दोनों ही

जरूरी हैं। पिछले वर्षों में राज्य में सतत विकास लक्ष्य में बेहतर काम किया गया है। एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड दसवें से चौथे स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि इससे अन्य लोग और संस्थाएं भी प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समाज और देश के लिये काम करने वाले व्यक्तियों से मिलकर प्रेरित होते हैं। इससे ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने सूखते जलस्रोतों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जलस्रोतों के रिचार्ज पर चल रहे काम को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसी तरह से उत्तराखण्ड की कला को भी प्रचारित किये जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे स्वयं विशिष्ट व्यक्तियों को ऐंपण कलाकृति भेंट करते हैं। सीपीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत ने बताया कि सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सराहनीय काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड देने के लिये पूर्व मुख्य सचिव श्री एन रविशंकर की अध्यक्षता में ज्यूरी का गठन किया गया था। कुल 176 आवेदन

प्राप्त हुए थे। इनके काम का भौतिक सत्यापन करते हुए ज्यूरी द्वारा 27 व्यक्तियों और

संस्थाओं का एसडीजी गोलकीपर अवार्ड के लिये चयन किया गया था।

एसडीजी 1 शून्य गरीबी के तहत कपिल तलवार, जनपद ऊधम सिंह नगर व हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर देहरादून, एसडीजी 2 शून्य भुखमरी के तहत बची सिंह बिष्ट, नैनीताल व हितैषी-हिमालयन पर्यावरण, जलस्रोत एवं पर्वतीय शिक्षा संस्था, बागेश्वर, एसडीजी 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के तहत सेवा इंटरनेशनल कर्णप्रयाग, चमोली, व उत्तराखण्ड एसोशियेशन फॉर पॉजिटिव पिपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स देहरादून, एसडीजी 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत संयुक्त रूप से चन्दन सिंह घुग्याल, देहरादून, जोगिंदर रोहिला देहरादून, व आसरा ट्रस्ट, देहरादून, एसडीजी 5 लैंगिक समानता के तहत, श्रीमती इंदिरा अधिकारी, अल्मोड़ा व हिमगिरी नैचुरल प्रोडक्ट्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अल्मोड़ा, एसडीजी 6 साफ पानी एवं स्वच्छता के तहत हिम्मोथान सोसाइटी, देहरादून, पेन हिमालयन ग्रासरूट डेव्लोपमेंट फाउंडेशन, अल्मोड़ा, एसडीजी 7: साफ और स्वच्छ ऊर्जा के तहत के. बी. सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ऊधम

सिंह नगर, एसडीजी 8 आर्थिक वृद्धि के तहत संयुक्त रूप से कैलाश पुष्पवान रूद्रप्रयाग, श्रीमती निमता तिवारी, अल्मोड़ा व पर्वतीय चाय उत्पादन स्वायत्त सहकारिता (बेरीनाग चाय), बेरीनाग, पिथौरागढ़, एसडीजी 9 उद्योग और नवाचार के तहत, मनमोहन भारद्वाज, हरिद्वार, एसडीजी 10: असमानताओं में कमी के तहत, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नैनीताल, एसडीजी 12 उपभोग और उत्पादन के तहत वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी, देहरादून, एसडीजी 13: जलवायु परिवर्तन के तहत अमित कुमार जैन, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन के तहत दिनेश गुरुनानी, पिथौरागढ़, एसडीजी 16 शांति और न्याय, संश्री तोष कुमार मासीवाल, अल्मोड़ा व रूरल इन्वियरमेन्टल एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसायटी चम्पावत, एसडीजी 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी के तहत सोसाइटी फॉर हिमालयन इन्वायरोमेंट एण्ड जिओलॉजी पिथौरागढ़, व द उम्मीद नेटवर्क, रूद्रप्रयाग और यंग एचीवर के तौर पर सिद्धार्थ माधव को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया।



गरीबों को अब मिला उनका हक : रेखा आर्य

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून: खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या जी ने आज विधानसभा में रअपात्र को ना, पात्र को हांर अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी तक राज्य में सरेंडर राशन कार्डों की जानकारी दी। माननीया रेखा आर्या ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि अब तक इस योजना के तहत राज्य में 58,374 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किये हैं जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में जाने - अनजाने में अपात्र राशनकार्ड धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे लेकिन अब पात्रों तक ये राशन पहुंचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है। माननीया मंत्री महोदया ने कहा कि ये राज्य में अभी तक का ऐसा पहला अभियान है जिसमें जनता का सकारात्मक रुख देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि PHH, SFY, और अन्त्योदय कार्ड धारकों में जिलेवार कई लोगों ने अपने कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किये हैं। माननीया मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूर्व में कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 मई निर्धारित की थी जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सकें।



माननीय मंत्री जी ने आगे बताया कि उनके द्वारा खाद्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है

कि सरेंडर कार्डों को अब पात्रों के बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।



अजय पंवार जैसे युवा कृषक उद्यमी, बन सकते हैं राज्य के युवाओं के लिए आदर्श : मंत्री गणेश जोशी

राज्य के 06 जनपदों के लगभग 4000 किसानों को बेहतर आय दिला रहे हैं अजय पंवार



तक पहुंचा रहे हैं।

कृषि मंत्री ने अजय पंवार को शुभकामनाएं दी तथा उम्मीद की कि उनकी टीम राज्य के किसानों को उत्पादन से विपणन तक एण्ड - टू - एण्ड साल्युशन उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने ऐसे युवा उद्यमियों को जो कि राज्य के व्यापक किसानों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं तथा पलायन की समस्या को भी संबोधित कर रहे हैं। सरकार की ओर से हर संभव सहयोग एवं सहायता का आश्वासन दिया। अजय पंवार ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्पादित होने वाले संबंध एवं औषधीय उत्पादों को इस स्तर के माध्यम

से वर्णन किया जायेगा। जिससे किसानों को अच्छी आमदनी मिल सके। वर्तमान में हम टिहरी जनपद के विकासखंड कीर्तिनगर, देवप्रयाग, थौलधार, नरेंद्रनगर, जाखणीधार, भिलंगना, प्रतापनगर के सैकड़ों किसानों की इससे जोड़ा है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर जनपदों के किसानों के साथ भी समर्थ एवं औषधीय पादपों की खेती कर रहे हैं। अजय पंवार ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके बड़े भाई महिपाल सिंह पंवार और धर्मपाल सिंह पंवार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिससे उनको और ऊर्जा मिलती है।

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, , रोजमैरी, लैवेंडर, डंडेलियों, थाइम, निपिता आदि समर्थ एवं औषधीय पादपों से निर्मित, इससेसियल ऑईल, हर्बल टी, तथा अन्य जैविक व स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के चकराता रोड़ स्थित स्टोर "कृषि, कृषक कल्याण" (3 के) का शुभारम्भ आज कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। स्टोर के संचालक अजय पंवार टिहरी जनपद के धार पाइयांकोटि के रहने वाले हैं और पिछले 6 सालों से समर्थ एवं औषधीय पादपों की खेती कर रहे हैं।

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जड़ी बूटी उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं। अजय पंवार जैसे युवा उद्यमी

राज्य के किसानों तथा युवाओं के लिए एक मिशाल पेश कर रहे हैं। जो अपने दशकों से बंजर पड़े खेतों को जड़ी बूटी एवं समर्थ एवं औषधीय पादपों की खेती से आबाद कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के कई किसानों को इस आधुनिक खेती से जोड़कर उनको रोजगार उपलब्ध करवाया है। अजय और उनकी टीम किसानों को इन फसलों की बुआई से लेकर विपणन तक के सभी चरणों में आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य तकनीकी सहयोग भी प्रदान कर रही है। इन औषधीय पादपों की जड़, पत्ते तथा फूल तक सभी की बाजार में भारी मांग है। इन लाभकारी पादपों से बनाए गए इससेसियल ऑईल तथा हर्बल टी को अजय और उनकी टीम भारत देश तथा विदेशों



रायवाला में देशी शराब की दुकान को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के विरोध में बीते छह दिनों से चल रहे धरने को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया समाप्त



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री अग्रवाल जी ने कहा कि शराब की दुकान किसी भी कीमत पर स्कूल मार्ग अथवा उसके समीप हरगिज नहीं खोली जाएगी। कहा कि इसी मार्ग से महिलाओं का भी आवागमन होता है, ऐसे में यहाँ अपराध बढ़ने की भी संभावना है। उन्होंने मौके पर से ही दूरभाष के जरिये जिलाधिकारी देहरादून डॉ आर राजेश कुमार से वार्ता की और ग्रामीणों की सहमती के बिना दुकान शिफ्ट करने की योजना पर नाराजगी जताई।

उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल इस सम्बंध में कार्यवाही करने को कहा। कहा कि शराब की दुकान किसी भी सूत्र में अन्यत्र जगह पर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका पालन करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मौके पर अग्रवाल जी ने ग्रामीणों का पिछले छह दिनों से चल रहा धरना समाप्त कराया। इस मौके पर धरने के नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान प्रतीतनगर अनिल कुमार ने कहा कि कैबिनेट व क्षेत्रीय विधायक ने सदैव जनता की समस्या का निदान किया है और ज्वलंत विषयों पर त्वरित गति से कार्यवाही भी की है। इसी समर्थन भाव के चलते जनता हर बार चुनाव में उनके जीत का अंतर बढ़ाती है। इस मौके पर धरना दे रहे सभी ग्रामीणों ने मंत्री अग्रवाल का आभार जताया। मौके पर मंत्री जी के समर्थन में जंदाबाद के नारे भी लगाये गए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुंग, ममता देवी,



कमला, प्रमिला देवी, देवेश्वरी, दीपा, सुनीता, उषा देवी, रेखा थापा, शारदा, चेता सिंह, सुनीता, दीपा, बबीता सैनी, विमला देवी, सुनीता दास, सोनिका देवी, एला देवी, कमला भंडारी, उर्मिला, पंचायत सदस्य अजय, सपना, रोशनी, सीमा, मीना बिष्ट, इंदु देवी, रमेश शाह सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने धरना समाप्त किया।

संपादकीय



मुद्रास्फीति से अभी राहत नहीं

पांच सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक ने दो चरणों में रेपो रेट में 90 बेसिस प्वाइंट (0.9 प्रतिशत) की बढ़ोतरी की है। रेपो रेट वह दर होता है, जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। अब यह दर 4.90 प्रतिशत हो गयी है। इस वृद्धि का मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी से अप्रैल के बीच मुद्रास्फीति में 170 बेसिस प्वाइंट की बढ़त हुई है। इसे देखते हुए देश के केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में आकलन किया था कि औसत खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 6.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 5.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 5.4 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2023) में 5.1 प्रतिशत हो सकती है। इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक को भरोसा है कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत (दो प्रतिशत कम या अधिक) के स्वीकृत स्तर पर रह सकती है। इस संदर्भ में एक गौरतलब बात यह है कि हाल के समय में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के इरादे से सस्ते दर पर ऋण मुहैया कराने की नीति वापस ले ली गयी है। हालांकि अभी भी रेपो रेट महामारी से पहले की दर से कम है, पर हालिया बढ़ोतरी का अर्थ यह है कि यह नीतिगत बदलाव भी हुआ है। ये निर्णय यह भी इंगित कर रहे हैं कि अंततः रिजर्व बैंक ने यह मान लिया है कि मुद्रास्फीति है। बीते दिसंबर तक यह तर्क दिया जा रहा था कि थोक मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं बढ़ रहा है, इसलिए खुदरा मुद्रास्फीति कम है। महामारी के दौरान पहले ही खुदरा महंगाई बहुत बढ़ गयी थी और अगर बाद में थोक मुद्रास्फीति में बढ़त हो रही है, तो देर-सबेर उसका असर खुदरा दामों पर पड़ना स्वाभाविक है। रिजर्व बैंक का मानना था, जो एक हद तक ठीक भी है, कि अगर आसान दरों पर धन बाजार में मुहैया किया जायेगा, तो लोग क्रेडिट लेंगे, निवेश करेंगे, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। बड़े उद्योगों ने कर्ज उठाया भी और इस क्षेत्र में सुधार भी सकारात्मक हुआ है, लेकिन मुश्किल सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के संबंध में है। अति लघु और लघु उद्यम बड़े पैमाने पर तबाह हुए हैं। यही वे क्षेत्र हैं, जो सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराते हैं। सस्ते कर्ज देने का एक आधार यह भी था कि अर्थव्यवस्था संतोषजनक गति से बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि बड़े उद्योग पटरी पर आ चुके हैं और सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में उनका हिस्सा अधिक है। विडंबना यह है कि जीडीपी में बड़े उद्योगों का बड़ा हिस्सा है, पर रोजगार में छोटे और मझोले उद्यमों का योगदान अधिक है। ऐसे में घरेलू बाजार में मांग भी सुस्त है और बाहरी कारणों- रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन से आपूर्ति में बाधा, अन्य भू-राजनीतिक कारक आदि- ने भी मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी कहा है कि बहुत जल्दी महंगाई से राहत मिलने की आशा नहीं है। जो मुद्रास्फीति के अनुमान हैं, उनमें भी एक पहलू यह है कि मानसून अगर सामान्य न रहा, तो आगे भी दबाव बना रहेगा। हालांकि यह एक अलग विषय है, पर इसका उल्लेख भी होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के बिबेक देबरॉय ने हाल ही में कहा है कि उनके ख्याल से, और यह हमारे जैसे कई अर्थशास्त्रियों का भी मानना है, पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे मांग बढ़ाने और मुद्रास्फीति कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। कई जानकार मानते हैं कि रेपो रेट बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये दरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों से कम रहेंगी, तो डॉलर देश से निकलने लगेगा। अभी स्थिति यह है कि विदेशी निवेशक कई कारणों से अपनी पूंजी वापस ले जा रहे हैं। और, इसे केवल दर बढ़ाकर नहीं रोका जा सकता है।

पाबौ ब्लाक के भट्टी गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी: विकासखंड पाबौ के भट्टी गांव के समीप लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। गश्त कर रहे वन कर्मियों को शुरुवार तड़के गुलदार पिंजड़े में कैद हुआ मिला। वन कर्मियों द्वारा गुलदार को पौड़ी स्थित विभाग के नागदेव रेंज लाया गया। जहां से गुलदार को रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर हरिद्वार भेज दिया गया है।

इससे पहले बीते दो जून को भट्टी गांव की एक बुजुर्ग महिला को गुलदार ने मार दिया था। तब क्षेत्र के ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गढ़वाल वन प्रभाग ने पूरी घटना की वस्तुस्थिति से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अवगत कराया गया। बाद में गांव के विभिन्न स्थानों पर पिंजरा लगाने के साथ गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं शूटर भी तैनात कर दिया गया। बताया गया कि शुरुवार तड़के वन कर्मी गश्त पर थे। इसी बीच उन्हें भट्टी गांव के समीप ही पिंजरे में एक गुलदार कैद हुआ मिला। इसकी सूचना वन कर्मियों ने अपने उच्चाधिकारियों को दी। बाद



में पिंजरे में कैद हुए गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया। वन क्षेत्राधिकारी अनिल भट्ट ने बताया कि उच्चाधिकारियों के गुलदार को रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर हरिद्वार भेज दिया गया है।

भट्टी गांव के समीप एक गुलदार के डूषपजड़े में कैद होने के बाद भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में और भी गुलदार होने की

आशंका जताई है। भट्टी गांव की ग्राम प्रधान सोनी पंत, माहेश्वरी देवी आदि का कहना है कि अभी भी क्षेत्र में गुलदारों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने गढ़वाल वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देकर अभी क्षेत्र में डूषपजड़ा लगाए रखने के अलावा शूटर यथावत रखने की मांग की है।

मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू, 12 या 13 जून को ले सकते हैं शपथ

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चंपावत उपचुनाव में 55 हजार से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले 12 या 13 जून को विधानसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं।

विधानसभा स्थित स्व. प्रकाश पंत भवन के सभागार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। 14 जून से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री 12 या 13 जून को विधानसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि अधिकारिक तौर पर शपथ की तारीख तय होनी बाकी है। विधानसभा सचिवालय की ओर से शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की ओर से मुख्यमंत्री को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने



चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री उपचुनाव जीत

कर सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है।

बदरीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, इस महीने बन सकता है यात्रा का नया रिकॉर्ड

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बदरीनाथ में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने यात्रा का नया रिकॉर्ड बन सकता है। जबकि यात्रा नवंबर तक चलती है। ऐसे में इस बार नया कीर्तिमान बनना तय है।

बदरीनाथ धाम की यात्रा आठ जून को शुरू हुई थी। बदरीनाथ में सबसे अधिक यात्री 2019 में पहुंचे थे। तब यह आंकड़ा 12 लाख से कुछ अधिक था। इस साल एक महीने में ही धाम में पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 6,09,695 हो चुकी है। यही क्रम बरकरार रहा तो जल्द ही सर्वाधिक यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन जाएगा।

कोरोना के दो साल बाद यात्रा शुरू होने पर प्रशासन के साथ ही बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भी यात्रियों की अधिक संख्या का अनुमान था। लेकिन इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि एक महीने में ही यात्रियों का आंकड़ा छह लाख के पार पहुंच जाएगा। यात्रियों की अधिक संख्या के चलते पुलिस, प्रशासन और बीकेटीसी को भी व्यवस्थाएं बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है।



केदारनाथ यात्रा पर पहुंची महाराष्ट्र की महिला यात्री संभाल जोशी (63) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 71 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जो वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक है। 2012 में पूरे यात्राकाल में 72 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी।

केदारनाथ मंदिर मार्ग पर तीन सौ मीटर लंबा वाटर प्रूफ रेन शेल्टर स्थापित कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रियों को घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश व तेज धूप से उन्हें दिक्कत हो रही थी। गोल चबूतरे से मंदिर परिसर की पहली सीढ़ी तक रेन सेल्टर स्थापित कर दिया गया है।

सिंचाई मंत्री महाराज ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की अधिकांश मांगों पूरी की

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ का द्वादश महाअधिवेशन



न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के एकीकरण में सिंचाई विभाग एक बड़ा विभाग है और इसके अधिकारियों, कर्मचारियों के हितों को किसी भी सूत्र में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के वर्तमान एड्रेस पिकचर में कोई कमी नहीं की जाएगी।

प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कॉलोनी स्थित अधिकारी क्लब में आयोजित उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के द्वादश महाअधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग प्रदेश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का आजादी के समय से ही सबसे महत्वपूर्ण विभाग रहा है 70 और 80 के दशक में पूरे देश में कई जला से वह जल विद्युत परियोजना सिंचाई विभाग के द्वारा ही बनाई गई जिससे क्षेत्र में हरित क्रांति आने के साथ-साथ देश आत्मनिर्भर बना।

उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के द्वादश अधिवेशन में 22 विषयों पर आधारित

मांग पत्र की अधिकांश मांगों सहमति जताते हैं हुए प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस मांगों पर भी शीघ्र विचार किया जाएगा। सिंचाई विभाग के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, इंजीनियरों और विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग के पास योजनाओं की कमी नहीं रहने दी जाएगी हमारा प्रयास होगा कि अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस संबंध में दीर्घकालीन नीति बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को पर्यटन से जोड़कर नई-नई योजनाएं तैयार की जाएंगी और इन योजनाओं को सिंचाई विभाग से संपादित करवाये जाने पर विचार किया जाएगा। सचिव सिंचाई व विभाग के अधिकारी, अन्य ऐसे विभाग जहां निर्माण कार्य हेतु इंजीनियरिंग कैडर स्ट्रक्चर नहीं है उन विभागों के काम सिंचाई विभाग से कराए जाने के लिए दोनों विभागों में समन्वय स्थापित कराने का

प्रयास किया जाएगा।

सिंचाई मंत्री महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में खाली पड़े कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। वर्तमान में लोक सेवा आयोग से निकली भर्ती के साथ इन रिक्त पदों को जोड़ने के लिए सचिव सिंचाई अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।

केदारनाथ धाम, नमामि गंगे योजना में घाटों के निर्माण एवं कुंभ मेला आदि में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सिंचाई मंत्री ने विभाग के इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा कि ट्रांसफर एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए सचिव सिंचाई संगठन के पदाधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक की जाएगी इसमें कर्मचारियों को अनिवार्य स्थानांतरण में दुर्गम से दुर्गम विकल्प देने का प्रावधान किया जाएगा।

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं

देते हुए कहा कि विभाग में कई कर्मचारी गंभीर बीमारियों के चलते अपनी तकलीफ को साझा नहीं कर पाते इसलिए सिंचाई विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को दुख तकलीफ के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सभी लोग आपस में तालमेल बनाकर विभागीय कार्यों को करें ताकि विभाग में स्वच्छ वातावरण के साथ साथ कार्य संस्कृति का निर्माण हो सके।

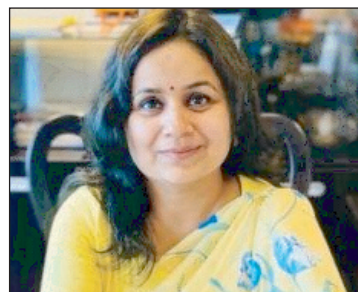
इस अवसर पर सिंचाई विभाग के संयुक्त सचिव जे.एल. शर्मा, प्रमुख अभियंता मुकेश मोहन, मुख्य अभियंता एवं संरक्षक एम.एल. नौटियाल, संघ के अध्यक्ष भरत सिंह डांगी, महासचिव अनिल सिंह पंवार, निवर्तमान अध्यक्ष हरीश नौटियाल, महासंघ के अध्यक्ष एस.एस. चौहान, महासचिव मुकेश रतूड़ी, वी.के. डंगवाल, कैलाश अनियाल, महिपाल सिंह डोभाल, मुकेश बहुगुणा, आनंद सिंह नेगी सहित विभागीय कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी व इंजीनियर उपस्थित थे।



स्वास्थ्य सचिव राधिका झा के निरीक्षण में मिली खामियां, दिए कड़े निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धित व्यवस्थाओं को देखने के लिये आई.एस.बी.टी. ऋषिकेश स्थित मेडिकल रिलीफ पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की रोटेशन ड्यूटी में लापरवाही पाये जाने पर सी.एम.ओ. देहरादून को कड़े निर्देश दिये गये कि कार्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा व्यवस्थाओं को अधिक बेहतर बनायें। सचिव ने निर्देश दिये कि चिकित्सा इकाई के द्वारा यात्रियों को दी जा रही सेवाओं की निगरानी के लिये वहां पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाय, तथा ई.सी.जी. सुविधा आवश्यक रूप में उपलब्ध रहे। पुलिस/एस.डी.आर.एफ. द्वारा संचालित



किए जा रहे रजिस्ट्रेशन काउण्टर के बारे में निर्देश दिए गये कि लाउडस्पीकर द्वारा हेल्थ स्क्रीनिंग हेतु यात्रियों से लगातार अनुरोध किया जाय तथा रजिस्ट्रेशन काउण्टर पर हेल्थ एडवाइजरी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। रजिस्ट्रेशन काउण्टर एवं हेल्थ स्क्रीनिंग में बेहतर समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए निर्देश दिये कि चिकित्सा इकाई पर तैनात फार्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ

पंजीकरण काउण्टर पर स्वयं जाकर बुजुर्ग एवं अस्वस्थ प्रतीत हो रहे यात्रियों को हेल्थ स्क्रीनिंग के लिये प्रोत्साहित करें और इस प्रकार के अस्वस्थ यात्रियों को आगे की यात्रा पर न जाने का परामर्श भी अवश्य दिया जाय। उन्होंने सी.एम.ओ को भद्रकाली एवं देहरादून एयरपोर्ट पर भी आवश्यकतानुसार हेल्थ स्क्रीनिंग उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य ने विभिन्न काउण्टरों एवं यात्री प्रतीक्षालय में स्वयं जाकर कई श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिसमें मध्यप्रदेश के 65 वर्षीय बुजुर्ग यात्री जो चारधाम यात्रा पूर्ण कर लौट रहे थे और यात्रा व्यवस्थाओं से खुश थे, ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी और जब वह छाती में दर्द होने पर चिकित्सालय गये तो उन्हें त्वरित उपचार मिला। इसी क्रम में सचिव राधिका झा ने एस.पी.एस. चिकित्सालय

ऋषिकेश का भी निरीक्षण किया जिसके दौरान मेडिसिन, बालरोग, प्रसूति एवं महिला रोग विभाग की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण में आयुष्मान योजना, कोविड टीकाकरण, तथा पैथोलॉजी के लाभार्थियों से बातचीत और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सचिव ने भ्रमण के दौरान अलग-अलग वार्डों में जाकर रोगियों से बातचीत की जिसमें सभी रोगियों ने अस्पताल की सेवाओं को संतोषजनक बताया। भ्रमण के दौरान आई.ए.एस. राधिका झा ने मरीजों के लिए भोजन एवं अस्पताल की साफ सफाई को भी देखा तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से कहा कि साफ सफाई एवं स्वच्छता को और बेहतर बनाया जाय। अन्ततः सचिव द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर का भी निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाये जाने के बारे में निर्देशित किया।

दैनिक
न्यूज़ वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटेर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :

मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी

दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com

RNI No.-UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा